Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

# हाईवे चैनल

वर्ष- 28 ◻ अंक- 144 ◻ रायपुर, बुधवार 18 जून 2025 ◻ पृष्ठ-8 ◻ मूल्य- 2.50 रुपया ● रायपुर ● जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

## अनुकम्पा नियुक्ति की कंडिका में किया गया संशोधन छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का होगा गठन

**रायपुर,** 18 जून (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. मानसून सत्र से पहले हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई. इसके बाद विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगी है. अनुकम्पा नियुक्ति की कंडिका में संशोधन किया गया है. साथ ही बाघों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी का गठन किया जाएगा.

मंत्रिपरिषद द्वारा शहीद पुलिसकर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकम्पा नियुक्ति हेतु जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश-2013 की कंडिका 13 (3) में संशोधन करते हुए निर्णय लिया है कि ङ्क नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य (महिला या पुरूष) को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा, किसी अन्य विभाग में, राज्य के किसी भी जिला, संभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी. पहले अनुकम्पा नियुक्ति यथासंभव उसी विभाग या कार्यालय में देने की व्यवस्था थी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक निधन के पूर्व कार्यरत था.

मंत्रिपरिषद ने राज्य में वन्यजीव, खासकर बाघों के संरक्षण और ईको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल करते हुए ''छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसायटी'' का गठन करने का निर्णय लिया है. यह सोसायटी वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत काम करेगी. मध्य प्रदेश में यह 1996 से संचालित है. इसका मुख्य लक्ष्य छत्तीसगढ़ में लगातार घट रही बाघों की आबादी (फिलहाल लगभग 18-20) को बचाना है.

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने और बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने

### साय कैबिनेट ने लिए कई महत्वपूर्ण फैसले

पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ-साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी, जो सोलर प्लांट की क्षमता (1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और उससे अधिक) के आधार पर अलग-अलग होगी. उदाहरण के लिए, 1 किलोवाट प्लांट के लिए कुल 45,000 रूपए, (30,000 रूपए केंद्रीय और 15,000 रूपए राज्य सहायता) जबकि 3 किलोवाट या उससे अधिक के प्लांट के लिए 1,08,000 रूपए (78,000 रूपए केंद्रीय और 30,000 रूपए राज्य सहायता) की मदद मिलेगी. मंत्रिपरिषद द्वारा अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था ''रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था ''विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ वेलफेयर एवं सेवायें, छत्तीसगढ़ (विश्वास)'' को रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में अंतर्भूत (मर्ज) करने का अनुमोदन किया गया.

उद्यानिकी महाविद्यालय (उद्यानिकी विश्वविद्यालय) की स्थापना के लिए बेमेतरा जिले के साजा तहसील अंतर्गत बेलगांव में राजगामी संपदा की 94.290 हेक्टेयर भूमि में से 100 एकड़ भूमि उद्यानिकी विभाग को निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

जशपुर जिले में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा हर्बल व महुआ चाय जैसे पारंपरिक उत्पाद 'JashPure' ब्रांड के तहत तैयार किए जा रहे हैं. इन उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और विपणन को बढ़ावा देने हेतु इस ब्रांड को राज्य शासन अथवा CSIDC को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव का मंत्री परिषद ने अनुमोदन किया है. ब्रांड हस्तांतरण से एग्रो व फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कच्चे माल की मांग बढ़ेगी और आदिवासी महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे. ट्रेडमार्क हस्तांतरण से राज्य पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा. मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति सूची में तकनीकी कारणों से शामिल होने से वंचित जातियों को प्राप्त होने वाली कतिपय सुविधाएं के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए डिहारी कोरवा, बघेल क्षत्री, संसारी उरांव तथा पबिया, पविया, पवीया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य एवं डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राज्य मद से मात्र राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किये जाने एवं छात्रावास-आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने की सहमति दी है. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में गौण खनिजों के सुव्यवस्थित अन्वेषण, पूर्वेक्षण एवं अधोसंरचना के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ''स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट'' (एसएमईटी) के गठन की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में स्टेट मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत समस्त गौण खनिजों से प्राप्त होने वाली रायल्टी 2 प्रतिशत राशि अतिरिक्त रूप से एसएमईटी फंड में जमा की जाएगी. जिसका उपयोग गौण खनिजों के अन्वेषण, अधोसंरचना विकास में उच्च तकनीकों का उपयोग, इन्फॉर्मेशन सिस्टिम, लॉजिस्टिक सपोर्ट, मानव संसाधनों के उन्नयन आदि में किया जा सकेगा. भारत सरकार के नेशनल मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की तर्ज पर राज्य में स्टेट मिनिरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट का गठन किया जाएगा.

## मारडेपल्ली के जंगल में मुठभेड़, नक्सली नेता उदय और चलपति की पत्नी अरुणा ढेर

**जगदलपुर,** 18 जून (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के सुकमा से लगे आंध्रप्रदेश के मारडेपल्ली के जंगल में नक्सलियों और ग्रेहाउंड्स फोर्स के बीच मुठभेड़ हुई है. एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों ने बड़े नक्सली लीडरों को ढेर कर बड़ी सफलता हासिल की है. दावा किया जा रहा है कि नक्सली कमांडर गाजरला उर्फ़ उदय और गरियाबंद में मारे गए खूंखार नक्सली चलपति की पत्नी वीआरएल चैतन्य उर्फ़ अरुणा को ढेर कर दिया गया है. इस अभियान में अबतक 2-3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है. इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है. पुलिस अधीक्षक अमित बरदार ने इसकी पुष्टि की है.

### ऑपरेशन जारी

जानकारी के मुताबिक, किंतुपुरु फॉरेस्ट क्षेत्र में तड़के सुबह से नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हो रही है. दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है. इस मुठभेड़ में जवानों ने तीन शीर्ष नक्सली कमांडर गिराए हैं. मौके से हथियार भी बरामद हुआ है. मुठभेड़ में गजराला और अरुणा के मारे जाने का दावा है. गजराला रवि ने 2004-05 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल के दौरान राज्य सरकार से शांति वार्ता में शामिल हुआ था. जबकि वे पीपुल्स वार ग्रुप का हिस्सा थे. वहीं अरुणा आंध्र प्रदेश ज़ोनल कमेटी की सदस्य थी.

### बड़े नक्सली लीडर ढेर

पुलिस का दावा है कि सुरक्षा बलों ने मारेडुमिल्ली और रामपचोदावरम के बीच स्थित किंतुकुरु गांव के पास 16 माओवादियों को ढेर कर दिया गया है. लगभग 25 मिनट तक चली गोलीबारी के बाद तीन शव बरामद हुए, जिनकी पहचान उदय, अरुणा और अंजू के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मौके से एके-47 राइफलें और अन्य हथियार बरामद किए गए हैं. अभी भी क्षेत्र में तलाश अभियान जारी है.

ग्रेहाउंड फोर्स की कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि यह संख्यात्मक विषय है, एक बार और स्पष्ट होने दिया जाए.

### गरियाबंद मुठभेड़ में मारा गया था खूंखार नक्सली चलपति

बता दें कि हाल में गरियाबंद जिले के सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 15 से अधिक नक्सली मारे गए थे. इसमें जयराम उर्फ चलपति भी शामिल था. चलपति नक्सलियों की सेंट्रल कमिटी का सदस्य था. चलापथी काफी खूंखार माना जाता था, इसलिए उस पर एक करोड़ रुपए का इनाम घोषित था. सीसी मेंबर जयराम उर्फ चलपति ओडिशा कैडर का नक्सली था, जो छत्तीसगढ़ में मारा गया था.

## ब्रेकिंग न्यूज

### उत्तराखंड : सुरंग में फंसे 40 श्रमिकों की जान खतरे में, अचानक ड्रिलिंग का काम रुका

नई दिल्ली, 18 जून (न्यूज चैनल)। निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में मलबे को भेदकर श्रमिकों तक पहुंचने का रास्ता बनाने के कार्य में फिर रुकावट आने से पिछले छह दिन से सुरंग में फंसे उन 40 श्रमिकों का इंतजार और बढ़ गया है जो बाहर निकाले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से शनिवार सुबह मिली जानकारी के अनुसार, फिलहाल सुरंग में ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है । इसके अनुसार, इंदौर से एक और भारी एवं शक्तिशाली ऑगर मशीन के आने का इंतजार किया जा रहा है। यह मशीन देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंच चुकी है जहां से इसे ट्रक के जरिए सिलक्यारा लाया जा रहा है। इससे पहले, सुरंग में मलबे को भेदने के लिए दिल्ली से एक अमेरिकी ऑगर मशीन लाई गयी थी जिसने शुक्रवार दोपहर तक 22 मीटर तक ड्रिलिंग कर चार पाइप डाल दिए थे। हालांकि, बाद में ड्रिलिंग का काम रुक गया। 12 नंवबर की सुबह हुए हादसे के बाद से लगातार चलाए जा रहे बचाव अभियान की जानकारी देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचआइडीसीएल) के निदेशक अंशु मनीष खाल्को ने शुक्रवार शाम कहा था कि मलबे में ड्रिलिंग कर छह मीटर लंबे चार पाइप डाल दिए गए हैं जबकि पांचवें पाइप को डालने की कार्रवाई चल रही है ।

## अब अंबेडकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में मरीजों की फोटो- वीडियो लेने पर रोक

**रायपुर,** 18 जून (हाईवे चैनल)। राज्य शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में रोगियों की फोटो-वीडियो लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है. जब तक रोगी या उसके कानूनी अभिभावक लिखित रूप से सहमति नहीं देंगे, तब तक अनुमति नहीं मिलेगी. इस आशय का आदेश मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किया. जारी आदेश के मुताबिक मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मीडिया प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित करने का हवाला दिया है, लेकिन इसे गत दिनों राजधानी के मेकाहारा अस्पताल में हुए बाउंसर विवाद से जोड़कर देखा जा रहा हैं.

चार पेज का उक्त आदेश सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा गत 13 जून को जारी किया गया, जो मंगलवार को सार्वजनिक हुआ है. उक्त आदेश में अस्पताल के अंदर रोगियों के वार्डों या संवेदनशील क्षेत्रों में मीडिया के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध निर्धारित किया है. इसी तरह किसी भी घटना या दुर्घटना के मामले में रोगियों के नाम, पहचान या चिकित्सा स्थिति का खुलासा नहीं किया जाएगा, जब तक कानून द्वारा आवश्यक न हो. इस आदेश में मीडिया के प्रवेश और कवरेज के लिए भी नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत मीडियाकर्मी पहले जनसंपर्क अधिकारी से अनुमति लेगा, फिर कवरेज क्षेत्र के जाएगा, किसी भी रोगी की बिनी अनुमति संवेदनशील जानकारी उजागर नहीं करेगा, लाइव रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित स्थान और समय निर्धारित रहेगा, ताकि अस्पताल के कामकाज पर इसका असर न हो. इतना ही नहीं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंद्ध चिकित्सालयों के संबंध में जो भी समाचार प्रकाशित होगा, उसकी वस्तुस्थिति से उसी दिन आयुक्त कार्यालय चिकित्सा शिक्षा विभाग को अवगत कराना अनिवार्य होगा. इस संबंध में 5 दिनों के भीतर में पालन प्रतिवेदन आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजना सुनिश्चित की जाए.

## 12 ग्रामीणों का अपहरण कर जंगल ले गए नक्सली, 3 को उतारा मौत के घाट

बीजापुर । छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने तीन ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया. आधा दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों के साथ मारपीट भी की गई. घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. पुलिस घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है. घटना बीजापुर थाना अंतर्गत ग्राम पेद्दाकोरमा की है.

जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों ने गांव के 12 लोगों का अपरहरण किया था. सभी को अपने साथ जंगल लेकर गए. जहां नक्सलियों ने तीन ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया. मृतकों की पहचान में जग्गू मोडियाम ,अनिल मंडावी, सोमा मोडियाम के रूप में हुई है. वहीं 7 ग्रामीणों को जमकर पीटा है. घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है.

### मुंबई पुलिस ने आदित्य ठाकरे के खिलाफ दर्ज की शिकायत

**नई दिल्ली,** 18 जून (न्यूज चैनल)। मुंबई पुलिस ने शिव सेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लोअर परेल में डेलिसले रोड ब्रिज का अवैध रूप से उद्घाटन करने के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया है। मुंबई नगर निगम के सड़क विभाग द्वारा एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई थी और उसके बाद आईपीसी की धारा 143, 149, 326 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मुंबई पुलिस के अनुसार, शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे, सचिन अहीर, पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर, पूर्व मेयर स्नेहल अंबेकर और 15-20 कार्यकर्ताओं के साथ स्थान पर गए और पुल का उद्घाटन किया। डेलिसल रोड ब्रिज यातायात के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था और मुंबई नगर निगम से पुल खोलने की कोई अनुमति नहीं थी। बीएमसी अधिकारी ने पुलिस से शिकायत की,

## 1 जुलाई से छत्तीसगढ़ में महंगी हो जाएगी जमीनें

**रायपुर,** 18 जून (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में जमीन की कीमतें जल्द ही बढ़ने वाली हैं. सूत्रों के मुताबिक, 1 जुलाई 2025 से जमीन की नई गाइडलाइन दरें लागू की जाएंगी. पंजीयन विभाग के सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइन दरों के लागू होने के बाद पूरे राज्य में जमीन की कीमतों में कम से कम 10-15त्न और कुछ क्षेत्रों में 20-25त्न तक की वृद्धि हो सकती है. सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जमीन के प्रचलित मूल्यों का आकलन किया है, जिसके आधार पर नई दरें तय की जाएंगी. रायपुर के 50 किलोमीटर के दायरे में जमीन की कीमतें सबसे अधिक बढ़ने की संभावना है.

पंजीयन विभाग ने प्रदेश के 33 जिलों में जमीन की मौजूदा बाजार दरों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और अब क्षेत्रवार व जिलेवार मूल्य विश्लेषण किया जा रहा है. पिछले कुछ महीनों में सर्वे में देरी के कारण नई दरें लागू करने में थोड़ा विलंब हुआ है. खास बात यह है कि राज्य में आठ साल बाद जमीन की गाइडलाइन दरों में बदलाव होने जा रहा है. नई गाइडलाइन दरों से सबसे अधिक फायदा किसानों को होगा. छत्तीसगढ़ में अधिकांश जमीनें किसानों के पास हैं. वर्तमान में सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मौजूदा गाइडलाइन दरों के आधार पर दिया जाता है, जबकि सड़क से सटी किसानों की जमीनों की वास्तविक कीमत गाइडलाइन से कई गुना अधिक है. नई दरें लागू होने के बाद सरकार को अधिग्रहण के लिए बढ़ी हुई दरों के हिसाब से मुआवजा देना होगा, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ होगा. जमीन के सौदों में अक्सर बड़े बिल्डर और डेवलपर गाइडलाइन दरों के बजाय अपनी मनमानी कीमत वसूलते हैं और अंतर की राशि नकद (कच्चे) में लेते हैं. इससे जमीन की वास्तविक कीमत को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है. नई दरें लागू होने से इस प्रथा पर अंकुश लगेगा, क्योंकि बढ़ी हुई गाइडलाइन दरें बाजार मूल्य के करीब होंगी, जिससे काले धन का लेन-देन कम होगा.

पिछले वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ को पंजीयन से 2,900 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है. उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र को पंजीयन से 40,000 करोड़, कर्नाटक को 30,000 करोड़ और मध्य प्रदेश के अकेले इंदौर शहर से 3,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलता है. नई गाइडलाइन दरें लागू होने से छत्तीसगढ़ में पंजीयन से मिलने वाले राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है. यदि औसतन 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो सरकार के खजाने में अतिरिक्त राशि आएगी, क्योंकि रजिस्ट्री अब बढ़ी हुई दरों पर होगी.

### केजरीवाल ने एलजी को भेजी विजलेंस मंत्री की रिपोर्ट, की चीफ सेक्रेटरी को तुरंत हटाने की मांग

**नई दिल्ली,** 18 जून (न्यूज चैनल)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सतर्कता मंत्री आतिशी की रिपोर्ट उपराज्यपाल को भेजी है, जिसमें मुख्य सचिव नरेश कुमार पर पद का इस्तेमाल करके बेटे की भागीदारी वाली कंपनी और आईएलबीएस के बीच लाभप्रद सहयोग कराने का आरोप लगाया गया है। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह रिपोर्ट बृहस्पतिवार को सतर्कता मंत्री ने केजरीवाल को सौंपी थी। रिपोर्ट में कुमार को निलंबित करने और मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की गई है। मुख्य सचिव के करीबी सूत्रों ने दावा किया है कि उनके बेटे ने कंपनी और आईएलबीएस के बीच किसी भी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उन्होंने दावा किया कि वह शेयरधारक, निदेशक, भागीदार या कर्मचारी के रूप में संबंधित कंपनी से बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं। यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान (आईएलबीएस) ने बृहस्पतिवार को एक बयान में आरोपों को पूरी तरह से निराधार और तथ्यहीन बताया था।

### बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, कांग्रेस नेता खेड़ा कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन में जाति जनगणना का जिक्र नहीं है।
चुहिया- हां जी, जाति-पांति पुछै नहीं कोई हरि को भजै सो हरि का होई...!